

स्टडी इन इंडिया से बदलेगी तस्वीर

पुष्कर
शिक्षाविद

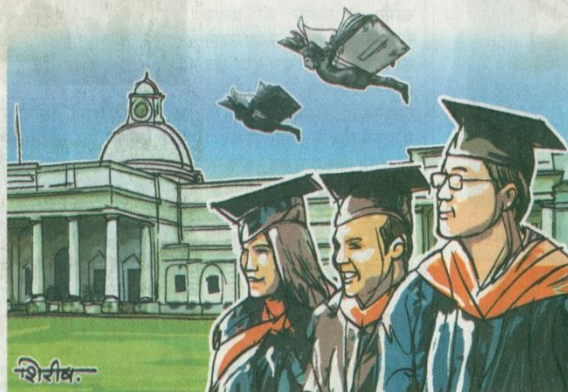


गोवा अंतरराष्ट्रीय संस्थान में निदेशक। मैकगिल विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो रहे।

आइआइटी संस्थानों ने सामूहिक स्तर पर विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति पर सहमति जताई है। आइआइटी काउंसिल ने तय किया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठित स्थापित आइआइटी संस्थान अपने और अपने सहयोगी संस्थानों के लिए एक अथवा अधिक भौगोलिक क्षेत्र से शिक्षक भर्ती के लिए जवाबदेह होगा।

विश्व रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के पिछड़ने का बड़ा कारण शोध अनुसंधान के संदर्भ में घटती संख्या व गुणवत्ता है। लेकिन बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीयकरण की कमी, खास तौर पर विदेशी छात्रों व अध्यापकों के संदर्भ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान इनमें शामिल हैं। भारत में करीब 903 विश्वविद्यालय और 50,000 कॉलेज व अन्य डिग्री प्रदाता संस्थान हैं। यहां करीब 3.60 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें विदेशी छात्रों की संख्या काफी कम है। भारत में विदेशी छात्रों की संख्या वर्ष 2010-11 में 27,531 थी जो 2017-18 में 46,144 हो गई। इस प्रकार 67 प्रतिशत की वृद्धि कई मायनों में अच्छा संकेत है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वर्ष 2017-18 में अमरीकी विवि में भारतीय छात्रों की संख्या 2 लाख से अधिक थी। 18 हजार से अधिक भारतीय छात्र चीन में पढ़ रहे हैं।

भले ही भारतीय विवि में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ रही हो पर यह अब भी कुल छात्र संख्या का 0.2 प्रतिशत ही है। भारत सरकार को यह अहसास काफी देर बाद हुआ कि विश्व रैंकिंग में स्थान बनाने के लिए भारतीय विवि को विदेशी छात्रों की आवश्यकता है। विदेशी छात्र और अध्यापक अधिकांशतः उच्च गुणवत्तापूर्ण विवि को ही पसंद करते हैं। सरकार ने 2016 में इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस यानी (आईआई) की स्थापना की। इनमें 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय शामिल किए गए। इन्हें विश्व मंच पर प्रोत्साहित किया जाएगा। आशा है भविष्य में ये विवि दुनिया के प्रमुख 100-200 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल होंगे। ये विवि 30 फीसदी तक विदेशी छात्रों को दाखिला और विदेशी अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं। वे जितने अधिक विदेशी छात्रों को पढ़ाएंगे, उनकी रैंकिंग में उतनी ही तेजी से सुधार की संभावना है। हालांकि फिलहाल इस दायरे में छह ही संस्थान शामिल किए गए हैं, ये



देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विदेशियों के रहने लिए अनुकूल वातावरण होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां नस्लीय भेद और अपराध की गुंजाइश न हो।

हैं-आइआइएससी, बेंगलूर, आइआइटी-बॉम्बे और आईआईटी-दिल्ली, सरकारी संस्थान और एजुकेशन और जियो इंस्टीट्यूट। भारत सरकार ने 2018 में 'स्टडी इन इंडिया' नामक पोर्टल की शुरुआत की। यह विदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय चुनने में सहायक होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार अगले पांच सालों में भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 2 लाख करने का लक्ष्य है। 15,000 सीटों में से 55 प्रतिशत सीटें एशिया-अफ्रीका के छात्रों को मैरिट के आधार पर अनुपातिक रूप से कम दरों पर आवंटित होंगी। आइआइटी काउंसिल ने तय किया है कि

विदेशी छात्रों की फीस निर्धारण के संदर्भ में आइआइटी ही निर्णय लेने को अधिकृत होंगे। ट्यूशन फीस कम कर आइआइटी दिल्ली ने विदेशी छात्रों को प्रवेश देने में बाजी मार ली है। 23 आइआइटी में केवल 40 विदेशी अध्यापक हैं। अब विश्वविद्यालयों को विदेशी शिक्षकों की भर्ती के लिए गृह व विदेश मंत्रालय से अनापत्ति पत्र की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान व पाकिस्तान के नागरिकों के लिए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है।

सरकार ने ऐसे भारतीयों, जिनके पास विदेशी पासपोर्ट है और जो ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया (द्वितीय पासपोर्ट के समतुल्य) के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी गृह व विदेश मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण लेने की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया है। आइआइटी संस्थानों ने सामूहिक स्तर पर विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति पर सहमति जताई है। आइआइटी काउंसिल ने तय किया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठित स्थापित आइआइटी संस्थान अपने और अपने सहयोगी संस्थानों के लिए एक अथवा अधिक भौगोलिक क्षेत्र से शिक्षक भर्ती के लिए जवाबदेह होगा। उदाहरण के लिए अमरीका को

तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हुए उसे आइआइटी बॉम्बे (पश्चिमी तट), आइआइटी दिल्ली (दक्षिणी अमरीका) और आइआइटी मद्रास (पूर्वी तट) में विभाजित कर दिया गया है। नीतियां भले ही कुछ जटिल लगें लेकिन एक संकेत साफ है कि आइआइटी बड़ी संख्या में विदेशी शिक्षकों की भर्ती को लेकर गंभीर हैं।

जहां तक विश्व रैंकिंग में सुधार का सवाल है, यह देखने में आ रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर गंभीर हैं। उदाहरण के लिए माना जा सकता है कि "स्टडी इन इंडिया" पोर्टल संभवतः बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को लुभाने में कामयाब न हो, इसलिए यह आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का विदेशों में प्रचार-प्रसार हो। वर्तमान में कुछ निजी विश्वविद्यालय अफ्रीकी देशों सहित कई विदेशी छात्रों को प्रवेश देने में सफल रहे लेकिन "स्टडी इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने के लिए कोई व्यापक सामूहिक नीति फिलहाल तैयार नहीं दिखती। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विश्वविद्यालयों में विदेशियों के रहने लिए अनुकूल वातावरण होना भी महत्वपूर्ण है, जहां नस्लीय भेद और अपराध की गुंजाइश न हो।

वेतन के बारे में बात की जाए तो आइआइटी जैसे संस्थान भी योग्य उम्मीदवारों को श्रेष्ठ वेतन देने में उतने सक्षम नहीं हैं, जितना होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से आइआइटी संस्थान दूर दराज के इलाकों में हैं, जहां बड़े शहरों जैसी सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती। इसलिए विदेशी मुश्किल से ही इनकी ओर आकर्षित होते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में स्थापित आइआइटी संस्थानों की समस्याएं एक दूसरे से काफी अलग हैं। जैसे दिल्ली का प्रदूषण अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है और विदेशियों को दिल्ली से विमुख करने के लिए काफी है। और सर्वोपरि कारण है भारतीय राजनीति जो विदेशी छात्रों को भारत आने से रोकने में अहम भूमिका निभा रहा है।